

राज्य वित्त: एक जोखिम विश्लेषण*

श्रीलंकाई संकट की पृष्ठभूमि में यह आलेख भारत में राज्य सरकारों के समक्ष आने वाले राजकोषीय जोखिमों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, जिसमें अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्यों पर जोर दिया गया है। स्व-कर राजस्व में मंदी, प्रतिबद्ध व्यय का एक उच्च हिस्सा और सब्सिडी के बढ़ते बोझ ने पहले ही कोविड द्वारा बढ़े हुए राज्य सरकार के वित्त को बढ़ा दिया है। गैर-मेरिट मुफ्त उपहारों (फ्रीबीज) पर बढ़ते खर्च, बढ़ती आकस्मिक देयताएं और डिस्कॉम के बढ़ते अतिदेय के रूप में जोखिम के नए स्रोत सामने उभर कर आए हैं।

भूमिका

लंबे समय तक कोविड महामारी संकट ने दुनिया भर की सरकारों की वित्तीय स्थिति को खराब कर दिया है, जैसा कि बढ़ते कर्ज के स्तर से परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर सार्वजनिक ऋण की स्थिरता ने पुनः प्रमुख वित्तीय जोखिम के रूप में अहम स्थान पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से, महामारी ने भारत में राज्यों के वित्त पर भारी असर डाला है, खास तौर पर अधिक गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के बीच मध्यावधि पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। इस विकट स्थिति को देखते हुए, सामान्य समय में नकद सब्सिडी देने की प्रवृत्ति, मुफ्त उपयोगी सेवाओं का प्रावधान, कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का पुनरुद्धार और भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निहित और स्पष्ट गारंटी का विस्तार सिर पर लटकती तलवार की तरह काम करता है।

यह आलेख भारत में राज्य सरकारों के सामने आने वाले राजकोषीय जोखिमों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, जिसमें अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्यों पर जोर दिया गया है। शेष आलेख चार भागों में संरचित है। खंड II विभिन्न असुरक्षितता संकेतकों के संदर्भ में भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का

* यह आलेख डॉ. माइकल देबब्रत पात्र के मार्गदर्शन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के डॉ. अत्री मुखर्जी, श्री समीर रंजन बेहरा, श्री सोमनाथ शर्मा, श्री बिचित्रानंद सेठ, श्री राहुल अग्रवाल, श्री रचित सोलंकी और सुश्री आयुषी खंडेलवाल द्वारा तैयार किया गया है। हम आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए कृतज्ञ हैं। आआलेख में व्यक्त किए गए विचार आलेखकों के हैं और आवश्यक नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को प्रतिनिधित्व करें।

आकलन करता है। खंड III राज्यों की कर्ज धारणीयता का मूल्यांकन अर्थमितीय रूप से परीक्षण करके करता है कि क्या वे ऋण शोधन क्षमता की स्थिति को पूरा करते हैं। जोखिम की पहचान के संदर्भ में, खंड IV जोखिम परिमाणीकरण और दबाव परीक्षण के माध्यम से वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों का विस्तृत जोखिम मूल्यांकन करता है। खंड V में निष्कर्षों और नीतिगत दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है।

II. भारतीय राज्यों की राजकोषीय असुरक्षितता

इस विश्लेषण को करने के लिए एक प्रमुख प्रेरणा श्रीलंका में संकट का आना है, जिसकी परिणति 19 मई 2022 को अपनी पहली ऋण चूक में हुई है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था महामारी से पस्त थी, क्योंकि यात्रा प्रतिबंधों ने पर्यटन को प्रभावित किया था; वैश्विक व्यापार में महामारी से प्रेरित मंदी के कारण कपड़ा, वस्त्र और चाय के निर्यात को झटका लगा; और वैश्विक वृद्धि में मंदी से विप्रेषण प्रभावित हुए थे। महामारी के अलावा, सार्वजनिक नीतियों ने भी संकट में योगदान दिया - महामारी से ठीक पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में तीव्र कटौती; उर्वरक सब्सिडी को बचाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर जैविक खेती में बदलाव, लेकिन इससे चावल के उत्पादन और बागान क्षेत्र की उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव हुए जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई और आवश्यक वस्तुओं की कमी आ गई; और चीन से महंगे कर्ज से वित्तपोषित महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं।

इस पृष्ठभूमि में, भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। महामारी की शुरुआत तक, राज्यों का औसत जीएफडी-जीडीपी¹ अनुपात वर्ष 2011-12 से 2019-20 के दौरान 2.5 प्रतिशत पर मामूली रहा, जो 3 प्रतिशत की राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) की सीमा से कम है। हालांकि, पर्याप्त अंतर-राज्यीय भिन्नताएं थीं - जबकि आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और राजस्थान में जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से अधिक की औसत जीएफडी थी, वहीं असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और दिल्ली का अनुपात 2 प्रतिशत से कम रहा²। राजस्व में तेज गिरावट, व्यय में वृद्धि और जीएसडीपी

¹ जीएफडी-जीडीपी अनुपात सकल राजकोषीय घाटे से सांकेतिक जीडीपी अनुपात को दर्शाता है।

² चूंकि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को वर्ष 2019-20 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, हमने इसे यहां शामिल नहीं किया है, भले ही इसका औसत जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 5.3 प्रतिशत था।

अनुपात के लिए कर्ज में तीव्र वृद्धि के साथ वर्ष 2020 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति तेजी से खराब हुई।

विश्लेषण के पहले चरण में, राजकोषीय असुरक्षितता की पहचान करने के लिए संकेतकों का एक पैनेल कार्यरत है³। वर्ष 2020-21 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात के आधार पर पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा - सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य थे। भारत में सभी राज्य सरकारों के कुल व्यय के लगभग आधे हिस्से के लिए ये 10 राज्य जिम्मेदार हैं (सारणी 1)। अन्य असुरक्षितता संकेतक भी इन 10 राज्यों को अपने क्रॉस हेयर में शुमार करते हैं। उनके राजस्व खातों (उत्तर प्रदेश और झारखंड को

छोड़कर) में घाटे के अलावा, उनका जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 2021-22 में 3 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक था। इसके अलावा, राज्यों के राजस्व पर कर्ज चुकाती के बोझ से निपटारे का एक उपाय - राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (आईपी-आरआर) अनुपात, इनमें से 8 राज्यों में 10 प्रतिशत से अधिक था⁵।

सभी संकेतकों से उभरने वाले चेतावनी संकेतों को ध्यान में रखते हुए, हम आवश्यक शर्त यानी कर्ज/ जीएसडीपी अनुपात द्वारा पहचाने गए 10 राज्यों में से अत्यधिक दबावग्रस्त राज्यों के एक मुख्य उपसमूह की पहचान कर सकते हैं। बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल अत्यधिक दबावग्रस्त राज्य हैं।

दस राज्यों में से आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब ने 15वें वित्त आयोग (एफसी-एक्सवी) द्वारा निर्धारित 2020-21

सारणी 1: राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22 सं.अ.	2022-23 ब.अ.	राज्यों का सापेक्ष आकार	2021-22 सं.अ.			
	कर्ज				राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा
आंध्र प्रदेश	35.5	32.5	32.8		14.3	3.2	1.6	1.4
बिहार	36.7	38.6	38.7		8.6	11.3	5.5	9.2
छत्तीसगढ़	26.3	26.2			8.0	3.8	0.3	2.1
गुजरात	21.0	19.0			14.2	1.5	0.0	0.2
हरियाणा	28.0	29.4			20.9	3.0	1.4	0.8
झारखंड	34.4	33.0	27.0		8.4	3.0	-0.1	1.3
कर्नाटक	22.4	26.6	27.5		14.3	2.8	0.4	1.3
केरल	37.1	37.0	37.2		18.8	4.2	2.6	1.7
मध्य प्रदेश	31.0	31.3	33.3		11.7	4.2	0.6	2.2
महाराष्ट्र	19.6	17.9	18.1		11.4	2.8	1.0	1.5
ओडिशा	20.0	18.8	18.6		4.3	3.5	-3.3	-0.6
पंजाब	49.1	53.3			21.3	4.6	1.6	0.7
राजस्थान	40.5	39.5	39.8		14.9	5.2	3.0	3.3
तमिलनाडु	26.9	27.4	27.7		21.0	3.8	2.5	1.9
तेलंगाना	25.2	24.7	25.3		11.3	3.9	-0.4	2.4
उत्तर प्रदेश	29.1	34.9	32.5		11.2	4.3	-1.3	1.8
पश्चिम बंगाल	37.1	34.4	34.2		20.8	3.5	2.2	1.1

← उच्चतर निम्नतर →

टिप्पणियाँ: 1. पंजाब के लिए डेटा 'राज्य वित्त: बजट 2021-22 का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट पर आधारित है क्योंकि वर्ष 2022-23 के लिए इसका बजट अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि 2022-23 के लिए ओडिशा का बजट लेखा अनुदान (वोट-ऑन-अकाउंट) है, इसने 2022-23 के लिए अपने एफआरबीएम दस्तावेज जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा दिये गए संकेत के अनुसार यदि सार्वजनिक खाता देयताओं को शामिल किया जाता है तो जीएसडीपी के 16.98 प्रतिशत का कर्ज स्टॉक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

2. अन्य राज्यों के लिए, कर्ज संबंधित डेटा, जीएफडी, आरडी और पीडी- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए जाते हैं और यह आवश्यक नहीं कि रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाने वाले डेटा से मेल खाएँ क्योंकि इन संकेतकों के संकलन की प्रकृति अलग-अलग होती है।

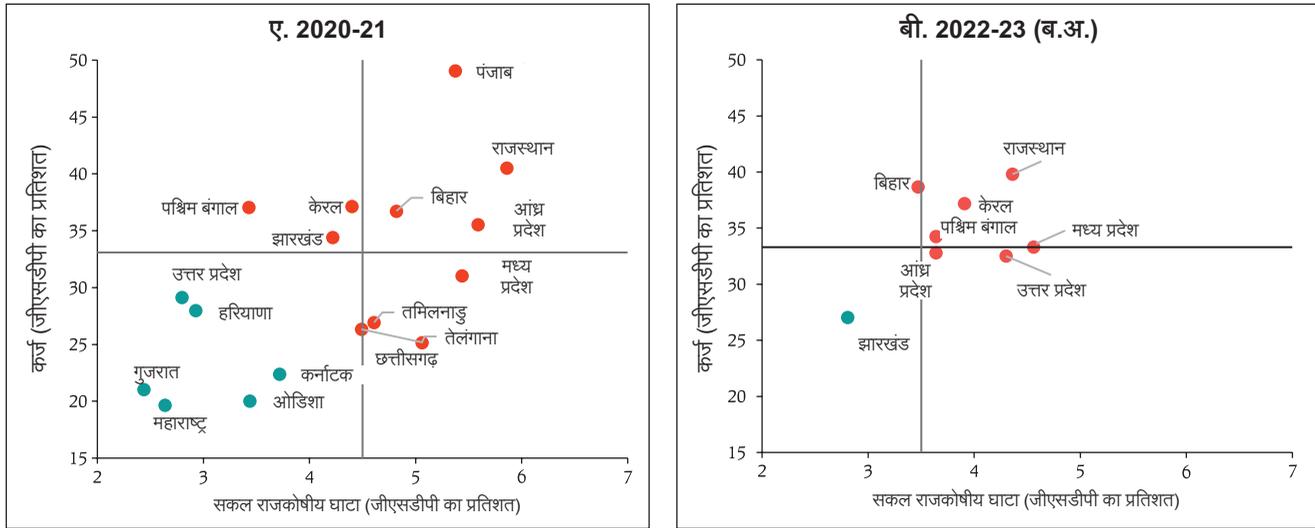
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज; भारतीय रिजर्व बैंक; और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च।

³ राजकोषीय असुरक्षितता एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जहाँ सरकार अपने समग्र राजकोषीय नीति उद्देश्यों और दीर्घकालिक राजकोषीय धारणीयता को पूरा करने में विफलता की संभावना के एक्सपोजर में है (आईएमएफ, 2000)।

⁴ वर्ष 2020-21 के आंकड़े लेखा आंकड़ों पर आधारित हैं। पंजाब को छोड़कर, उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनकी विशेष विशेषताओं को देखते हुए विश्लेषण से बाहर रखा गया है। कुल व्यय में निम्न हिस्सेदारी के कारण गोवा को भी इससे बाहर रखा गया है।

⁵ बिहार और झारखंड का आईपी-आरआर अनुपात 10 प्रतिशत से कम है।

चार्ट 1: 15वें वित्त आयोग के सांकेतिक लक्ष्य की तुलना में राज्यों के प्रमुख संकेतक



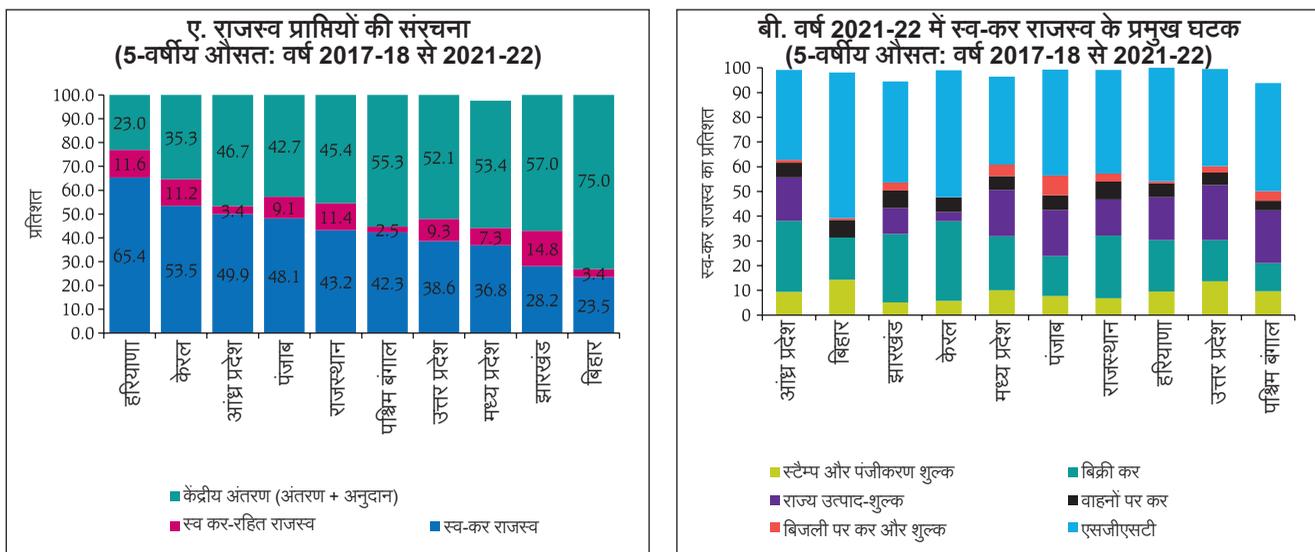
टिप्पणी: ग्राफ के अंदर समस्तर और ऊर्ध्वाधर लाइनें क्रमशः कर्ज और जीएफडी के लिए 15वें एफसी के सांकेतिक लक्ष्य हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

के लिए कर्ज और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, दोनों को पार कर लिया है (चार्ट 1ए)। केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने कर्ज लक्ष्य को पार कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर लिया। अपवादस्वरूप, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने दोनों मानदंडों को पूरा किया था। राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2022-23 (ब.अ.) में कर्ज और राजकोषीय घाटे के लिए एफसी-एक्सवी लक्ष्यों को पार करने का अनुमान है (चार्ट 1बी)।

सरकारी राजस्व

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एकत्र किए गए कुल राजस्व में से लगभग आधी हिस्सेदारी दस चयनित राज्यों की है। उनके कुल राजस्व में कर राजस्व, कर-रहित राजस्व और केंद्रीय हस्तांतरण यानी केंद्रीय करों और अनुदानों में हिस्सा, शामिल हैं (चार्ट 2ए)। हरियाणा, केरल और आंध्र प्रदेश का स्व-कर राजस्व उनके कुल राजस्व संग्रह का लगभग आधा हिस्सा है।

चार्ट 2: राज्यों की कर संरचना



स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

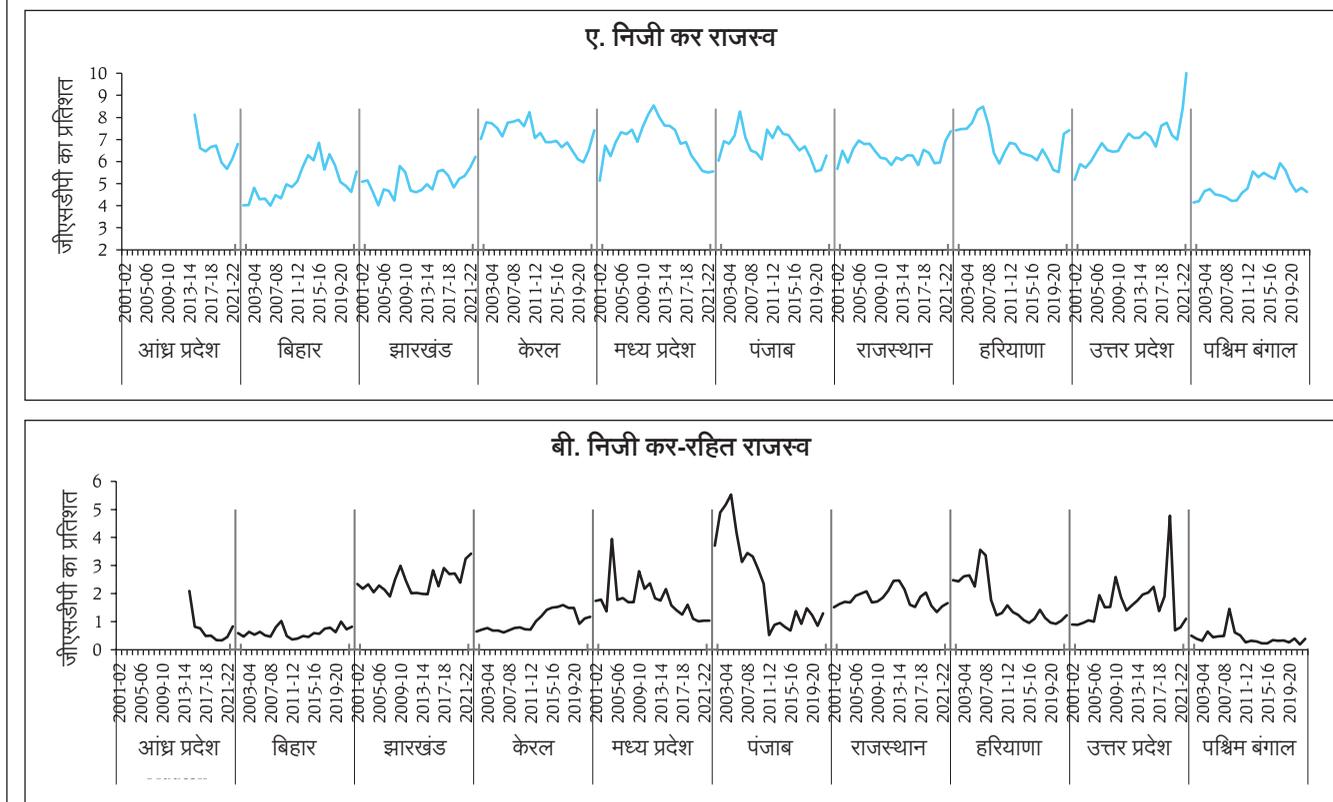
अन्य राज्यों के राजस्व का प्रमुख स्रोत केंद्रीय हस्तांतरण है। स्व-कर राजस्व के अंतर्गत, राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी), राज्यों के उत्पाद शुल्क और बिक्री कर राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं (चार्ट 2बी)।

इन 10 राज्यों में से कुछ का, अर्थात् मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल, स्व-कर राजस्व समय के साथ घट रहा है, जिससे वे वित्तीय रूप से अधिक असुरक्षित हो गए हैं (चार्ट 3ए)। इनमें से अधिकांश राज्यों के लिए, कर-रहित राजस्व अस्थिर रहा है, हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय रूप से कमी आ रही है (चार्ट 3बी)। सामान्य सेवाओं, ब्याज प्राप्तियों और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कर-रहित राजस्व में गिरावट आई है। राज्यों की व्यय योजना को घटते स्व-कर राजस्व और कर-रहित राजस्व प्रभावित करते हैं और बाजार उधार पर उनकी निर्भरता को बढ़ाते हैं।

व्यय गुणवत्ता

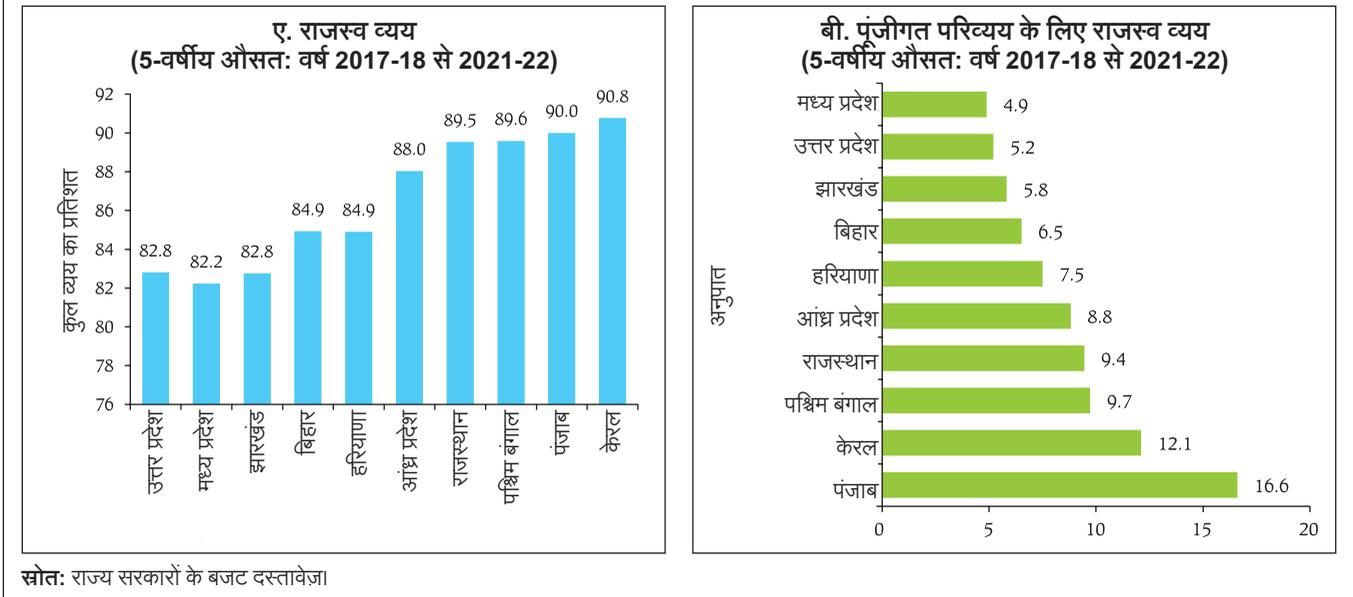
असुरक्षितता संकेतकों द्वारा पहचाने गए 10 राज्यों की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल व्यय में लगभग आधी हिस्सेदारी है। इन राज्यों के कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 80-90 प्रतिशत की सीमा में भिन्न-भिन्न होता है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे कुछ राज्य राजस्व खातों में लगभग 90 प्रतिशत व्यय करते हैं (चार्ट 4ए)। ऐसे में ये खराब व्यय गुणवत्ता में परिणत होते हैं, जैसा कि पूंजीगत परिव्यय अनुपात में उनके उच्च राजस्व व्यय से परिलक्षित होता है (चार्ट 4बी)। हालांकि कल्याणकारी, आर्थिक गतिविधियों पर राजस्व व्यय का प्रभाव लगभग एक वर्ष तक ही रहता है। इसके विपरीत, पूंजीगत परिव्यय का प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है और लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिसका चरम प्रभाव दो-तीन वर्षों के बाद होता है। मध्यम से दीर्घावधि में, उच्च राजस्व व्यय और निम्न

चार्ट 3: राज्यों का कर और कर-रहित स्व-राजस्व



स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

चार्ट 4: राजस्व व्यय और व्यय की गुणवत्ता

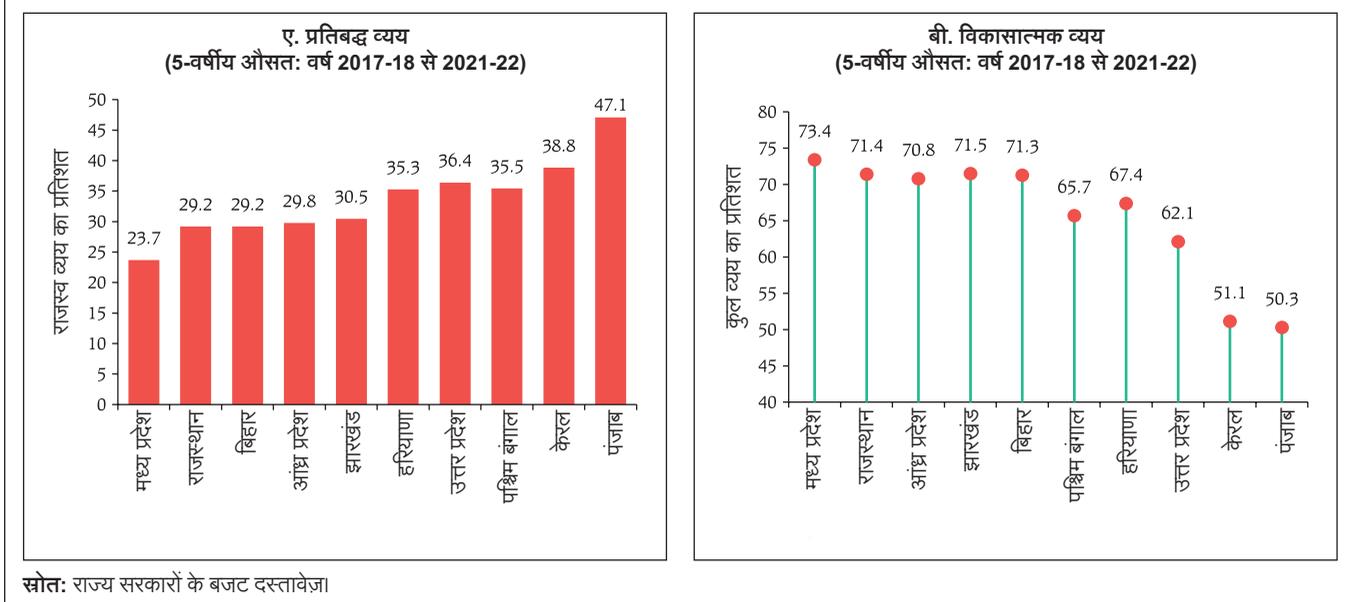


पूंजी निवेश वाले राज्यों को मंद राजस्व वृद्धि और उच्च ब्याज व्यय का सामना करना पड़ सकता है।

प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में कुल राजस्व

व्यय के एक महत्वपूर्ण हिस्से (35 प्रतिशत से अधिक) के लिए उत्तरदायी है, जिससे विकासात्मक व्यय करने के लिए सीमित राजकोषीय गुंजाइश बचती है (चार्ट 5ए)। परिणामस्वरूप, इन राज्यों में विकासात्मक व्यय का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है (चार्ट 5बी)।

चार्ट 5: राज्यों के व्यय संबंधी संकेतक



सारणी 2: राज्य-वार 10-वर्षीय एसडीएल प्रतिफल

(प्रतिशत)

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	7.6	7.6	8.3	7.2	6.5	
बिहार	7.4	8.0	8.3	7.1		7.2
छत्तीसगढ़	7.7	7.9		7.3		
गुजरात	7.6	7.7	8.3	7.3	6.7	7.0
हरियाणा	7.4	7.8	8.5	7.2	7.4	7.0
झारखंड	7.4	7.3	8.4	7.0	6.8	6.9
कर्नाटक	7.3	7.7	8.2	7.1	6.6	7.0
केरल	7.6	7.8	8.3	7.4	7.2	7.1
मध्य प्रदेश	7.4	7.6	8.3	7.2	6.9	6.9
महाराष्ट्र	7.5	7.4	8.3	7.3	7.0	6.8
ओडिशा	7.4	7.7	8.2	7.1		
पंजाब	7.8	7.7	8.3	7.3	6.8	7.0
राजस्थान	7.5	7.8	8.4	7.4	6.7	7.0
तमिलनाडु	7.5	7.7	8.3	7.4	6.7	7.0
तेलंगाना	7.7			7.7	7.0	
उत्तर प्रदेश	7.5	7.7	8.4	7.2	6.9	7.0
पश्चिम बंगाल	7.5	7.8	8.3	7.2	6.7	7.1

← उच्चतर निम्नतर →



स्रोत: आरबीआई।

एसडीएल प्रतिफल

मामूली अंतरराज्यीय प्रसार के बावजूद, राज्यों के राजकोषीय निष्पादन और एसडीएल प्रतिफल के मध्य एक

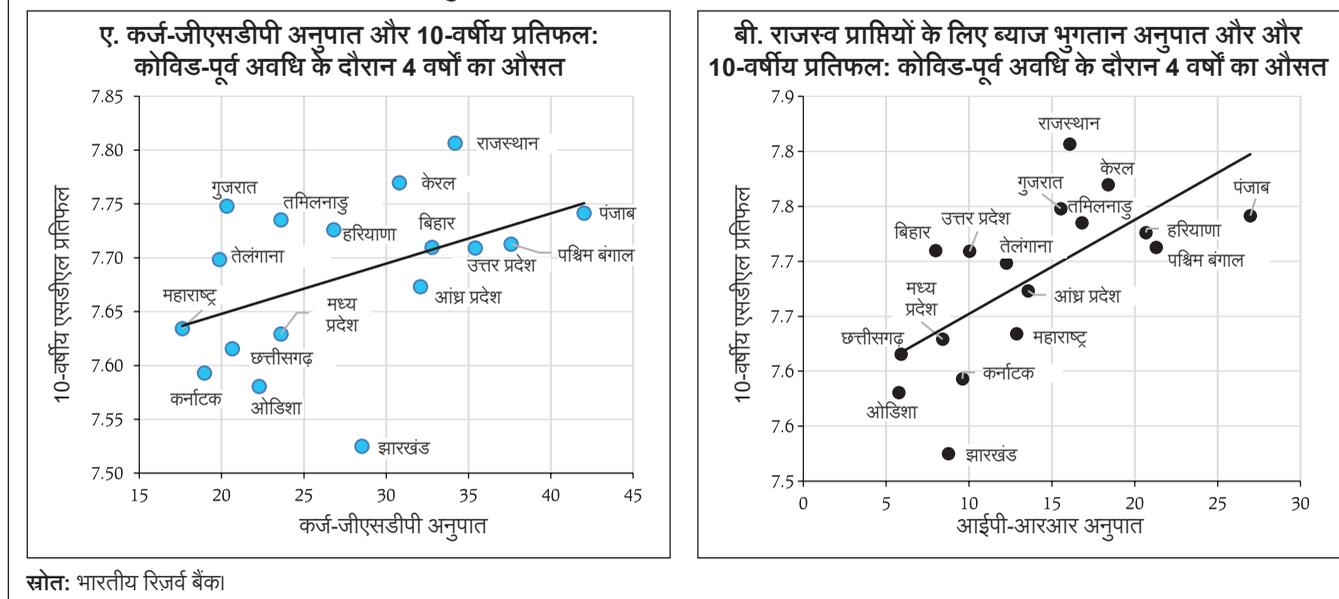
विपरीत संबंध है (सारणी 2)। उदाहरण के लिए, उच्च कर्ज-जीएसडीपी अनुपात और उच्च आईपी-आरआर अनुपात वाले वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों में एसडीएल प्रतिफल अधिक होता है (चार्ट 6)। एसडीएल रेटिंग के अभाव में, ये राजकोषीय स्थितियां एसडीएल प्रतिफल के निर्धारण में एक विभेदक फिल्टर की भूमिका निभाती दिख रही हैं।

इसलिए अपनी उधारी की लागत को कम करने के लिए, राज्यों के लिए अपनी राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है।

III. कमजोर राज्यों की कर्ज धारणीयता

आईएमएफ का राजकोषीय जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन फ्रेमवर्क⁶ कर्ज धारणीयता और राजकोषीय दबाव का आकलन करने में सहायता करने के लिए एक राजकोषीय प्रतिक्रिया कार्य (फिस्कल रिएक्शन फंक्शन - एफआरएफ) प्रदान करता है। व्यवसाय चक्र के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को दर्शाने के लिए एफआरएफ वर्तमान आर्थिक स्थितियों के लिए लेखांकन करते हुए प्राथमिक शेष राशि को कर्ज से जोड़कर ऋण-शोधन क्षमता का आकलन करता है (आईएमएफ, 2016; बोह, 1998; एडम्स, और अन्य, 2010; तिवारी, 2012; कौर, और अन्य, 2018)। जब

चार्ट 6: प्रमुख वित्तीय संकेतक और 10-वर्षीय एसडीएल प्रतिफल



⁶ आईएमएफ (2016)। वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण और प्रबंधन - सर्वोत्तम अभ्यास।

प्राथमिक शेष (जीडीपी के सापेक्ष) सार्वजनिक ऋण (जीडीपी के सापेक्ष) के समान रहता है, तो इसका तात्पर्य है कि बढ़ते कर्ज अनुपात से उच्च प्राथमिक अधिशेष होता है जिसका उपयोग कर्ज की चुकौती और इसकी सर्विसिंग के लिए किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कर्ज धारणीयता। इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, वर्ष 2001-02 से 2021-22 तक वार्षिक डेटा वाले पैनेल डेटा फ्रेमवर्क में निम्नलिखित समीकरण का अनुमान लगाया गया है:

$$S_{i,t} = \alpha_0 + \beta D_{i,t-1} + \alpha_1 GSDPGAP_{i,t} + \alpha_2 EXPGAP_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad \dots(1)$$

जहां जीएसडीपी से तात्पर्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद है; एस- जीएसडीपी अनुपात का प्राथमिक शेष है; डी- जीएसडीपी अनुपात के लिए कर्ज है, जिसमें स्पष्ट गारंटी के रूप में आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं; जीएसडीपीजीएपी अपनी प्रवृत्ति से वास्तविक उत्पादन का विचलन है; ईएक्सपीजीएपी अपनी प्रवृत्ति से वास्तविक प्राथमिक व्यय का विचलन है; और त्रुटि पद है। 'β' ब्याज का गुणांक है क्योंकि यह कर्ज के प्रति प्राथमिक शेष की प्रतिक्रिया को मापता है। शून्य और एक के बीच किसी गुणांक मान से तात्पर्य है कि वर्तमान अवधि में कर्ज-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि से बाद की अवधि में प्राथमिक शेष में वृद्धि होती है, जो ऋण के लिए एक स्थायी राजकोषीय नीति समायोजन के अनुरूप है। दूसरी ओर, एक ऋणात्मक गुणांक इंगित करता है कि प्रतिक्रिया अस्थिर हो सकती है क्योंकि चालू वर्ष में कर्ज अनुपात में वृद्धि से अगले वर्ष प्राथमिक अधिशेष में गिरावट आती है, जिससे कर्ज चुकौती मुश्किल हो जाती है।

समीकरण 1 का अनुमान (i) सभी राज्यों⁷ के लिए लगाया गया है; (ii) 10 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य; और (iii) 5 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य⁸। राज्यों का निष्पादन वर्ष 2020-21 में कर्ज-जीएसडीपी अनुपात (खंड 2 में सारणी 1 और सारणी 3⁹) पर आधारित है।

परिणाम दर्शाते हैं कि सभी राज्यों और 10 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों के लिए, व्याख्यात्मक चर के सभी गुणांक

⁷ उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्यों और तेलंगाना को छोड़कर, जिनके आंकड़े 2014-15 से ही उपलब्ध हैं।

⁸ वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर, भारत में शीर्ष 5 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य हैं निम्न: पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के अलावा, शीर्ष 10 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों में निम्न शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा।

⁹ हॉसमैन परीक्षण के परिणामों ने इंगित किया कि डेटासेट के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल, निश्चित प्रभाव मॉडल है।

सारणी 3: अनुमान परिणाम

व्याख्यात्मक चर	अनुमानित गुणांक		
	सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	10 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य	5 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य
1	2	3	4
स्थिर	-3.65*** (0.00)	-2.87*** (0.00)	1.54 (0.59)
डी _{t-1}	0.07*** (0.00)	0.04*** (0.00)	-0.09 (0.24)
जीएसडीपीजीएपी _t	3.53*** (0.00)	3.22* (0.08)	5.79 (0.26)
एक्सपीजीएपी _t	-9.63*** (0.00)	-7.92*** (0.00)	-13.14*** (0.00)
एआर (1)	0.46*** (0.00)	0.44*** (0.00)	0.38** (0.02)
समायोजित आर ²	0.50	0.40	0.62
डीडब्ल्यू	1.99	2.02	1.68

टिप्पणियाँ: 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित पी-मान को दर्शाते हैं।

2) ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तरों पर महत्व को दर्शाते हैं।

सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं और प्राथमिकता की अपेक्षाओं के अनुसार सही संकेत हैं। 5 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए प्राप्त D_{t-1} के धनात्मक गुणांक से पता चलता है कि राज्य सरकारों का प्राथमिक शेष आम तौर पर बढ़ते कर्ज अनुपात के जवाब में बढ़ता है, जो कर्ज धारणीयता का संकेत है।

पांच सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों के लिए D_{t-1} का गुणांक ऋणात्मक निकला, हालांकि इसमें सांख्यिकीय महत्व का अभाव है, जिसका अर्थ है कि बढ़ते कर्ज अनुपात का इन राज्यों के प्राथमिक शेष अनुपात पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जबकि भारत में राज्य सरकारों का कुल कर्ज अभी भी धारणीय है, पांच सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों का सार्वजनिक ऋण, धारणीयता की स्थिति की पूर्ति नहीं करता है।

इन पांच राज्यों के कर्ज धारणीयता के विभिन्न संकेतकों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2020-21 को छोड़कर, डोमर स्थिरता की स्थिति (कर्ज पर वास्तविक ब्याज दर¹⁰ वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर से कम होनी चाहिए; आर-जी (r-g) < 0) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन राज्यों में पूरी हुई थी (सारणी 4)। दूसरी

¹⁰ मुद्रास्फीति के लिए समायोजित प्रभावी ब्याज दर।

सारणी 4: कर्ज धारणीयता संकेतक					
राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
आर-जी (प्रतिशत अंक)					
बिहार	-6.2	-6.0	2.3	-3.4	-3.5
केरल	-4.6	3.3	10.8	-5.4	-3.0
पंजाब	-0.5	2.9	7.9	-2.4	
राजस्थान	-1.8	-2.0	5.7	-11.2	-5.5
पश्चिम बंगाल	-5.3	-1.8	-0.1	-10.5	-4.1
सांकेतिक जीएसडीपी और कर्ज वृद्धि में अंतर (प्रतिशत अंक)					
बिहार	5.0	-2.0	-11.4	-5.5	-0.3
केरल	-0.2	-5.2	-17.1	0.5	-0.6
पंजाब	0.2	-2.9	-12.9	1.4	
राजस्थान	-1.2	-3.7	-14.2	2.9	-0.7
पश्चिम बंगाल	4.0	-0.6	-4.9	8.4	0.6

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

ओर, पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर अधिकांश समय जीएसडीपी वृद्धि से अधिक रही है, जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में कर्ज-जीएसडीपी अनुपात बढ़ रहा है।

IV. राज्यों का राजकोषीय जोखिम विश्लेषण

एक सुदृढ़ राजकोषीय जोखिम विश्लेषण फ्रेमवर्क में, संभावित स्रोतों और वित्तीय जोखिमों की प्रकृति की पहचान करना, राजकोषीय जोखिम की मात्रा का निर्धारण करना और अपनाने के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की अनुशंसा करना महत्वपूर्ण है।

IV.1 जोखिम पहचान

राजकोषीय जोखिम समष्टि-आर्थिक आघातों और आकस्मिक देयताओं की वसूली से उत्पन्न हो सकते हैं। आकस्मिक देयताएं या तो 'स्पष्ट' हो सकती हैं, अर्थात् सरकारी ऋण गारंटी, या 'अंतर्निहित', जिसमें बिना किसी विशिष्ट गारंटी के भी, जनता की व्यापक प्रत्याशा है कि सरकार संकटग्रस्त संस्थाओं को बचाएगी या उन्हें राहत देगी। विश्व स्तर पर, आकस्मिक देयताओं के सबसे आम स्रोत संकटग्रस्त वित्तीय संस्थान, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, उप-राष्ट्रीय सरकारें, निजी गैर-वित्तीय कंपनियां और सार्वजनिक-निजी भागीदारी हैं,

क्योंकि सरकार को डिफॉल्ट के मामले में चूककर्ता इकाई में किसी भी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी या स्वामित्व के बिना इन संस्थाओं को बचाना या बेलआउट करना होता है (आईएमएफ, 2016)। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाएं अक्सर राजकोषीय जोखिमों को बढ़ा देती हैं, जो अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए तैनात राजकोषीय प्रतिक्रियाओं की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है। हालांकि, यदा-कदा कानूनी मामले कई बार महत्वपूर्ण राजकोषीय जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

भारत में राज्य सरकारों के समक्ष प्रमुख समष्टि-आर्थिक जोखिम, वर्तमान में विकसित हो रही कोविड स्थिति के आसपास की अनिश्चितताओं, उच्च वैश्विक खाद्य और पण्य वस्तुओं की कीमतों के माध्यम से संचालित रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव-विस्तार और दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा समकालिक मौद्रिक सख्ती से उत्पन्न होते हैं। इन समष्टि-आर्थिक आघातों के अलावा, भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय जोखिम के अन्य संभावित स्रोत स्व-कर राजस्व में गिरावट, "मुफ्त उपहारों" के वितरण के लिए बढ़ती प्राथमिकता के कारण व्यय में वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को दी गई सरकारी गारंटियों की वसूली और घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बढ़ती बकाया राशि से उपजे हैं।

पेंशन व्यय

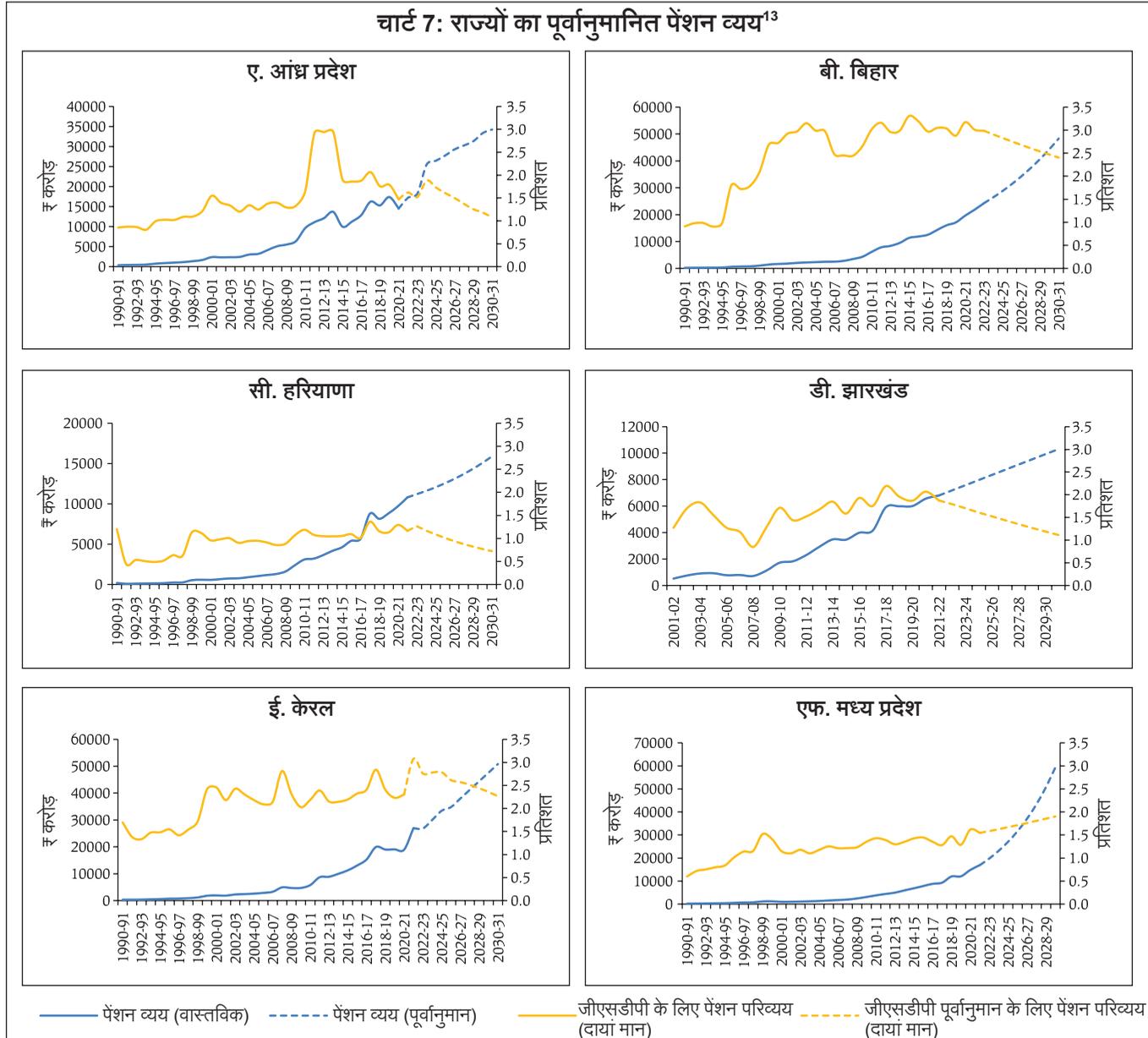
पुरानी पेंशन प्रणाली (परिभाषित लाभ) - मुख्य रूप से एक पे-एज-यू-गो प्रणाली और इसलिए, बिना फंड वाली - में कई कमियां थीं, विशेष रूप से मध्यम अवधि के वित्तीय स्थिरता और भविष्य की पीढ़ियों पर कर के बोझ के संदर्भ में। कई राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने यह महसूस करने के बाद कि पुरानी प्रणाली लंबे समय में टिकाऊ नहीं थी, नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बदल गई थी।¹² हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर पदों के उलटफेर ने एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नुकसान के बारे में बहस छेड़ दी है तथा कुछ और राज्य कथित तौर पर इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

¹¹ आईएमएफ (2016)। "वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण और प्रबंधन - सर्वोत्तम अभ्यास"। आईएमएफ पॉलिसी पेपर।

¹² केरल ने 2013 में एनपीएस को अपनाया और पश्चिम बंगाल ने एनपीएस को नहीं अपनाया।

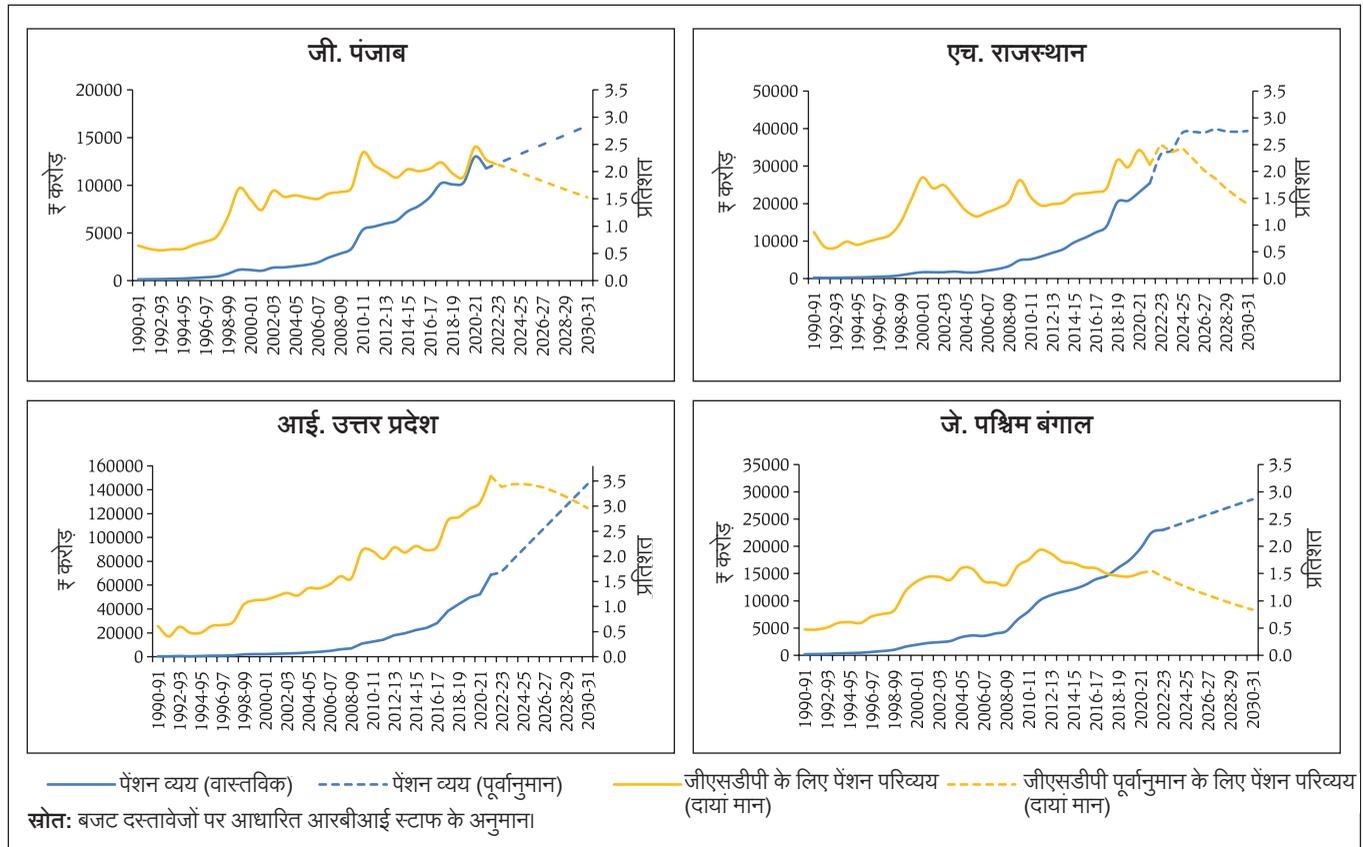
10 सर्वाधिक ऋणग्रस्त राज्यों के कुल राजस्व व्यय में केवल पेंशन व्यय 12.4 प्रतिशत (2017-18 से 2021-22 का औसत) के लिए जिम्मेदार है। यह अनुमान है कि पेंशन व्यय सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.7-3.0 प्रतिशत की सीमा में बना रहेगा

(चार्ट 7)। चूंकि वर्तमान राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, यदि राज्य पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने का विकल्प चुनते हैं तो तत्काल वित्तीय दबाव महसूस नहीं किया जाएगा।



(जारी)

¹³ वर्ष 2020-21 से पहले के पिछले पांच वर्षों की औसत वृद्धि दर का उपयोग करते हुए राज्यों के जीएसडीपी 2021-22 से 2029-30 तक अनुमानित हैं। वर्ष 2021-22 से 2029-30 तक आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए पेंशन व्यय पूर्वानुमान इन राज्यों के मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरणों (एमटीएफपीएस) से लिया गया है। पश्चिम बंगाल के लिए, 2023-24 तक पेंशन व्यय पूर्वानुमान एमटीएफपीएस से लिया गया है (पश्चिम बंगाल के लिए, एमटीएफपीएस 2023-24 तक पेंशन आउटगो प्रोजेक्शन प्रदान करता है)। झारखंड, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (2024-25 से 2029-30 तक) के पेंशन व्यय का अनुमान 1990-91 के ऐतिहासिक डेटा पर एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एल्गोरिथम का उपयोग करके 2021-22 से 2029-30 तक लगाया गया है।



हालांकि, जब एनपीएस के तहत वर्ष 2004-05 के बाद शामिल हुए राज्य सरकार के कर्मचारी वर्ष 2034 से सेवानिवृत्त होने लगेंगे, तो इस तरह के कदम का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पुरानी पेंशन योजना को अपनाने से भावी पीढ़ियों की कीमत पर वर्तमान पीढ़ी को लाभ होने की संभावना है।

राज्य सब्सिडी और मुफ्त उपहार

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में कमी के बाद, 2020-21 और 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर राज्य सरकारों का खर्च क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत बढ़ा है (चार्ट 8ए)¹⁴। इसी अनुपात में, राज्यों द्वारा कुल राजस्व व्यय में सब्सिडी का हिस्सा भी 2019-20 में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 8.2 प्रतिशत हो गया है। अलग-अलग स्तर पर, राज्यों के बीच काफी भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच राज्य हैं,

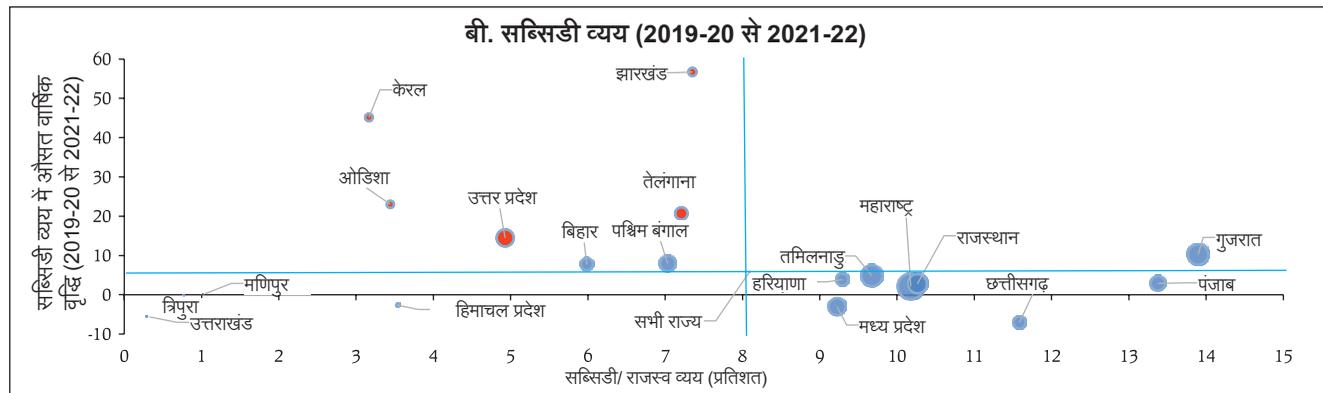
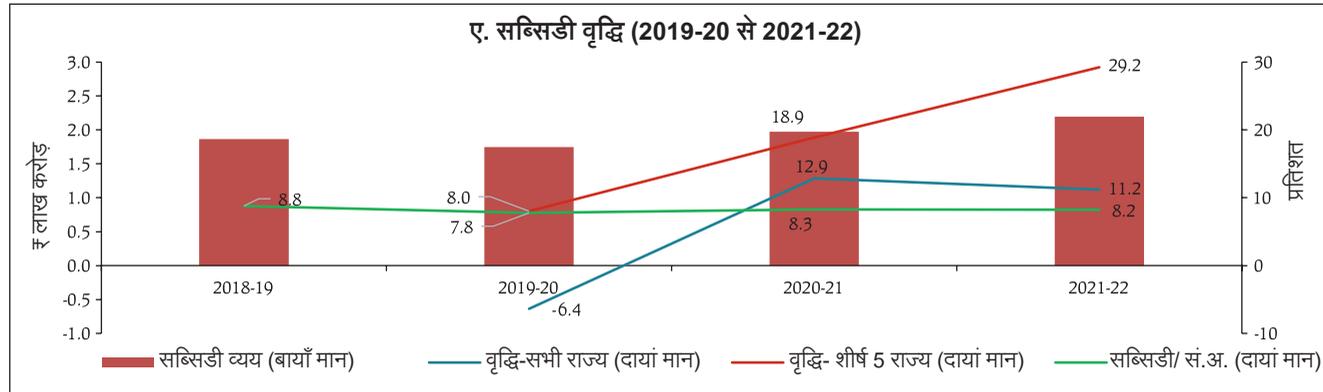
जहां पिछले तीन वर्षों में सब्सिडी में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपने राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी पर खर्च करते हैं (चार्ट 8बी)। हालांकि, सब्सिडी को अन्य उपयोगी उद्देश्यों से संसाधनों को बाहर निकालने के लिए जाना जाता है (गोपालन, 2013)।

हाल की अवधि में, राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडी का एक हिस्सा मुफ्त में देना शुरू कर दिया है¹⁵। जबकि मुफ्त उपहारों की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, उन्हें सार्वजनिक/ योग्य वस्तुओं से अलग करना आवश्यक है, जिस पर होने वाले व्यय से आर्थिक लाभ होता है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्यों का समर्थन (सिंह, 2022)। दूसरी ओर मुफ्त बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन, लंबित उपयोगिता बिलों की माफी और कृषि ऋण माफी के प्रावधान को अक्सर मुफ्त उपहार के रूप में समझा जाता है, जो संभावित रूप से क्रेडिट संस्कृति को कमजोर करते हैं, निजी

¹⁴ 19 राज्यों के संबंध में।

¹⁵ एक लोक कल्याणकारी उपाय जो निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

चार्ट 8: राज्यों का सब्सिडी व्यय



टिप्पणी: डेटा 19 राज्यों से संबंधित है जिनके लिए मासिक सब्सिडी व्यय डेटा मार्च 2022 तक उपलब्ध है। बुलबुलों का आकार वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान कुल सब्सिडी व्यय के अनुरूप है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)।

निवेश के लिए प्रोत्साहन को कम करते हुए क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से कीमतों को विकृत करते हैं, और मौजूदा वेतन दर पर काम को हतोत्साहित करने के कारण श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आती है। कुछ मुफ्त उपहारों को न्यूनतम क्षरण के साथ उचित रूप से लक्षित किए जाने पर गरीब वर्ग लाभान्वित हो सकता है, लेकिन उनके लाभों का मूल्यांकन उनके द्वारा विकृत कीमतों और संसाधनों के गलत आबंटन के कारण बड़ी राजकोषीय लागतों और अक्षमताओं के मद्देनजर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह सर्वविदित है कि मुफ्त बिजली और पानी के प्रावधानों से पर्यावरणीय क्षरण और जल स्तर में कमी में तेजी आती है।

मुफ्त उपहारों का अनुमान लगाने के लिए, हमने राज्यों द्वारा अपने नवीनतम बजट भाषणों (यानी 2022-23 के लिए) में घोषित प्रमुख वित्तीय सहायता/ नकद हस्तांतरण, उपयोगी वस्तुओं पर सब्सिडी, ऋण या शुल्क छूट और ब्याज मुक्त ऋण पर डेटा एकत्र

किया है। इन अनुमानों के अनुसार, विभिन्न राज्यों के लिए मुफ्त उपहारों पर व्यय जीएसडीपी के 0.1 - 2.7 प्रतिशत के बीच है (सारणी 5)। आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ अत्यधिक ऋणग्रस्त

सारणी 5: वर्ष 2022-23 में राज्यों द्वारा घोषित मुफ्त उपहार

	(जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	(राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में)	(स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2.1	14.1	30.3
बिहार	0.1	0.6	2.7
हरियाणा	0.1	0.6	0.9
झारखंड	1.7	8.0	26.7
केरल	0	0	0.1
मध्य प्रदेश	1.6	10.8	28.8
पंजाब*	2.7	17.8	45.4
राजस्थान	0.6	3.9	8.6
पश्चिम बंगाल	1.1	9.5	23.8

*: धरमाना, आई. (2022)। "सभी राज्य आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं हैं कि वे मुफ्त की घोषणा नहीं कर सकते।" बिजनेस स्टैंडर्ड, अप्रैल 2022।

स्रोत: राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

राज्यों के लिए मुफ्त उपहार जीएसडीपी के 2 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं (अनुबंध 1)।

केंद्र का जीएसटी मुआवजा भुगतान जून 2022 में समाप्त हो जाएगा, जिससे सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए उपलब्ध गुंजाइश में और कमी आएगी। ऐसी स्थिति में, मुफ्त उपहारों के रूप में कई सामाजिक कल्याण योजनाएं न केवल सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेगी, बल्कि बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित होने पर प्रतिफल पर भी दबाव डालेगी। इसलिए, राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे लाभार्थियों को स्थायी रूप से सशक्त बनाने और ऐसे लाभों को त्यागने को सुनिश्चित करके अधिकतम दीर्घकालिक कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने व्यय को प्राथमिकता दें। साथ ही, राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र की योजना के लिए एक अंतिम सीमा हो। केवल योग्य व्यक्तियों तक सब्सिडी पहुंचाना सुनिश्चित करने से सब्सिडी की मात्रा कम होगी, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अनुसंधान एवं विकास और ग्रामीण अवसंरचना में निवेश करने के लिए संसाधन प्राप्त होंगे तथा अधिक रोजगार सृजित करने और स्थायी आधार पर गरीबी को कम करने में सहायता मिलेगी (गुलाटी 2022)।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं सरकार के संविदात्मक दायित्व हैं जो उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, या तो

उधार ली गई मूल राशि या ऐसी राशि या दोनों पर ब्याज भुगतान पर भुगतान करते हैं। हाल के वर्षों में राज्यों की आकस्मिक देयताएं बढ़ रही हैं। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों द्वारा बजटेतर उधार - राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा उठाए गए और राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण - वर्ष 2022 में जीडीपी के लगभग 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है (क्रिसिल, 2022)। जबकि इन गारंटियों का लगभग 40 प्रतिशत बिजली क्षेत्र का है, अन्य लाभार्थियों में सिंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, खाद्य और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आकस्मिक देयताओं ने जीएसडीपी के 5 प्रतिशत को पार कर लिया है (सारणी 6)।

डिस्कॉम बेलआउट

भारत में सब्सिडी और आकस्मिक देयताओं, दोनों के मामले में, राज्य सरकारों के अधिकांश वित्तीय बोझ के लिए बिजली क्षेत्र जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर, कई राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के एक वर्ग के लिए बिजली की लागत को कृत्रिम रूप से कम करके सब्सिडी प्रदान करती हैं। राज्य सरकारें भी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में इक्विटी और ऋण के माध्यम से पूंजी का निवेश करती हैं ताकि वे उत्पादक निवेश कर सकें। इसके अतिरिक्त, आवधिक बेलआउट (पिछले 20 वर्षों में डिस्कॉम के 3 बेलआउट¹⁶) जिसमें राज्य या तो नुकसान उठाते हैं या डिस्कॉम के कर्ज के बोझ का राज्य के वित्त पर अच्छा-खासा दुष्प्रभाव पड़ता है।

सारणी 6: राज्य सरकारों द्वारा जारी गारंटियां (जीएसडीपी का प्रतिशत)

	बिहार	केरल	पंजाब	राजस्थान	पश्चिम बंगाल	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश	हरियाणा
2017-18	1.1	2.5	4.5	7.5	0.9	4.6	6.3	2.2
2018-19	1.0	3.4	0.9	7.6	0.6	6.2	6.9	2.6
2019-20	0.9	3.2	4.1	8.1	0.5	8.1	6.7	2.7
2020-21 (सं.अ.)	3.4	3.9	5.3	8.6	0.6	9.0	8.0	NA

एनए: उपलब्ध नहीं

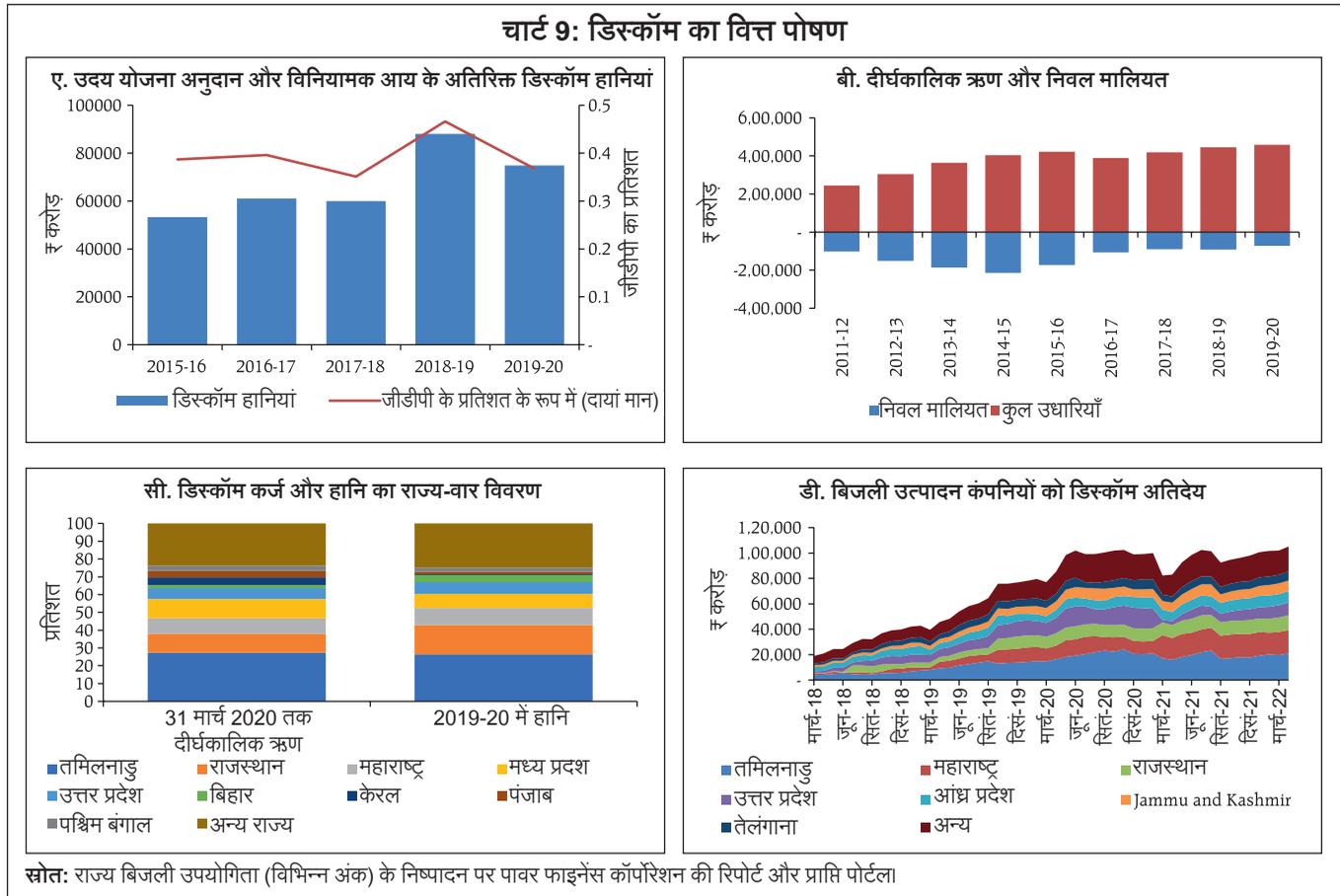
स्रोत: राज्य सरकार के बजट दस्तावेज; राज्य सरकारें; और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (पीआरएस)।

¹⁶ वर्ष 2003 में एकमुश्त निपटान, 2012 में वित्तीय पुनर्चना योजना और 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)।

विभिन्न वित्तीय पुनर्रचना उपायों¹⁷ के बावजूद, डिस्कॉम का निष्पादन कमजोर रहा है, उनके हानि 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत के उदय योजना के पूर्व स्तर को पार कर गए (चार्ट 9ए)। इसके अलावा, उनका दीर्घावधि ऋण वर्ष 2017-18 से बढ़ना शुरू हो गया, 2018-19 तक उदय योजना के पूर्व स्तर को पार कर गया और 2019-20 में और बढ़ गया (चार्ट 9बी)। पांच सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों, यथा बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में डिस्कॉम की संयुक्त हानि, 2019-20 में कुल डिस्कॉम के नुकसान का 24.7 प्रतिशत थी

जबकि उनका संयुक्त दीर्घावधि कर्ज वर्ष 2019-20 में कुल डिस्कॉम कर्ज का 22.9 प्रतिशत था (चार्ट 9सी)। इसके अलावा, बिजली उत्पादन कंपनियों (जीईएनसीओ) की डिस्कॉम के लिए बकाया राशि मार्च 2018 से बढ़ गई है (डिस्कॉम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त चलनिधि के कारण नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान कुछ सामान्यता आई)¹⁸, जिससे इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नए चलनिधि अंतर्वेशन की आवश्यकता हो सकती है (चार्ट 9डी)।

चार्ट 9: डिस्कॉम का वित्त पोषण



¹⁷ पहला बेलआउट प्रकरण 2003 में हुआ, जब राज्य सरकारों ने बिजली बांड जारी करने के माध्यम से केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि का भुगतान किया। दूसरे उदाहरण में, राज्य सरकारों को डिस्कॉम को अपने अल्पकालिक कर्ज दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 2012 में एक वित्तीय पुनर्रचना योजना शुरू करनी पड़ी। तीन बेलआउट में से तीसरी और सबसे महत्वाकांक्षी 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना थी, जिसके तहत राज्य सरकारों ने डिस्कॉम की बकाया देयताओं के 75 प्रतिशत हिस्से का अधिग्रहण कर लिया।

¹⁸ योजना के तहत, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बकाया देय राशि को समाप्त करने के लिए डिस्कॉम को दीर्घावधि संक्रमण ऋण (10 वर्ष तक) के ₹1.35 लाख करोड़ मंजूर किए, जिसमें से 31 दिसंबर 2021 तक ₹1.03 लाख करोड़ का वितरण किया गया था। डिस्कॉम की बकाया राशि फिर से बढ़ने के साथ, मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा एक दूसरी पहल की घोषणा की गई, जिसमें उत्पादन कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी गई, बशर्ते डिस्कॉम 48 किशतों में अपने बकाया का भुगतान करें।

डिस्कॉम के लिए बचाव पैकेज, राज्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि: (i) डिस्कॉम के दीर्घावधि कर्ज का 75 प्रतिशत (मार्च 2020 के अंत तक) का जिम्मा राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है (उदय योजना के समान); और (ii) राज्य अप्रैल 2022 तक जेनको को बकाया राशि के अनुसार डिस्कॉम में चलनिधि (इक्विटी के रूप में) अंतर्वेशित करते हैं, राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा। 18 प्रमुख राज्यों के लिए बेलआउट की लागत उनके संयुक्त जीएसडीपी का 2.3 प्रतिशत होगी, हालांकि राज्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब संभावित

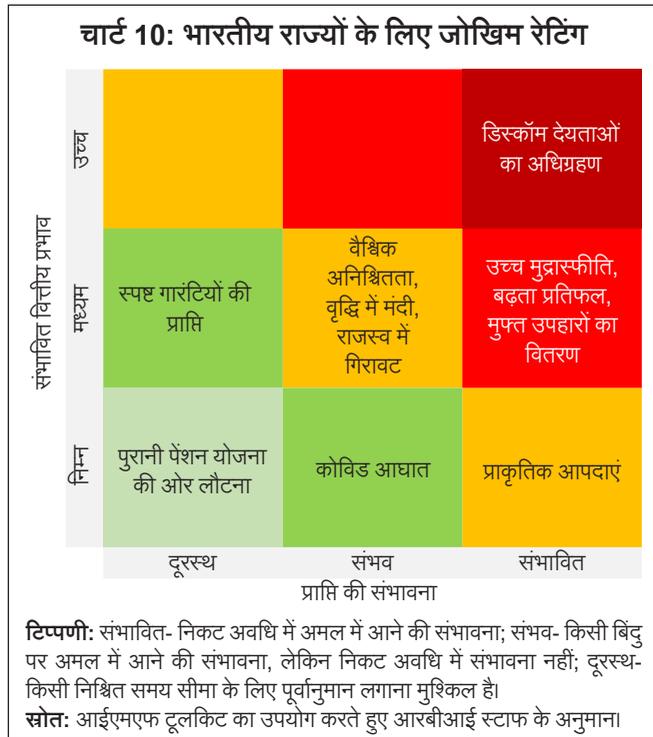
बेलआउट के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं जबकि गुजरात, असम, हरियाणा और ओडिशा इस जोखिम से अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं (सारणी 7)। ऐसे बेलआउट से बचने के लिए, डिस्कॉम को आगे चलकर उचित टैरिफ संशोधन करने की आवश्यकता है जो आयातित कोयले की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति की अंतर्निहित लागत को दर्शाता है।

स्रोतों, प्रकृति और जोखिमों की मात्रा के आधार पर राज्य सरकारों की समग्र जोखिम रेटिंग को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है (चार्ट 10)।

सारणी 7: प्रमुख राज्यों में डिस्कॉम के संभावित बेलआउट का प्रभाव

राज्य	बेलआउट से पूर्व		बेलआउट का आकार		बेलआउट के बाद		बेलआउट का कुल आकार	
	दीर्घावधि कर्ज	इक्विटी	दीर्घावधि कर्ज के 75% हिस्से की अवधारणा	बिजली खरीद अतिदेय के लिए चलनिधि का अंतर्वेशन	दीर्घावधि कर्ज	इक्विटी	2020-21 की जीएसडीपी का प्रतिशत	
	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़		
पंजाब	16,258	22,417	12,194	1,404	4,065	36,015	13,598	2.5
राजस्थान	48,934	-46,282	36,701	11,543	12,234	1,962	48,244	3.7
पश्चिम बंगाल	14,222	16,430	10,667	677	3,556	27,774	11,344	0.9
केरल	20,310	-5,581	15,233	493	5,078	10,145	15,726	1.8
बिहार	6,726	21,603	5,045	755	1,682	27,403	5,800	0.8
आंध्र प्रदेश	26,810	-19,810	20,108	8,914	6,703	9,212	29,022	2.1
उत्तर प्रदेश	28,782	8,368	21,587	10,195	7,196	40,150	31,782	1.3
झारखंड	10,530	2,889	7,898	3,643	2,633	14,430	11,541	2.5
हरियाणा	6,864	1,347	5,148	919	1,716	7,414	6,067	0.7
तमिलनाडु	1,24,413	-72,411	93,310	21,038	31,103	41,937	1,14,348	5.2
ओडिशा	4,599	-5,948	3,449	321	1,150	-2,178	3,770	0.6
छत्तीसगढ़	4,102	-2,896	3,077	191	1,026	372	3,268	0.9
तेलंगाना	21,948	-23,363	16,461	7,201	5,487	299	23,662	1.7
मध्य प्रदेश	49,112	-31,090	36,834	5,240	12,278	10,984	42,074	3.9
असम	2,429	8,457	1,822	45	607	10,324	1,867	0.5
कर्नाटक	22,767	3,232	17,075	4,304	5,692	24,611	21,379	1.0
गुजरात	563	16,607	422	715	141	17,744	1,137	0.0
महाराष्ट्र	39,086	29,135	29,315	18,392	9,772	76,842	47,707	1.0
उपरोक्त राज्यों के लिए कुल	4,48,455	-76,896	3,36,341	95,990	1,12,114	3,55,435	4,32,331	2.3

स्रोत: राज्य बिजली उपयोगिता (विभिन्न अंक) के निष्पादन पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट, प्राप्ति पोर्टल और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।



IV.2 ऋण पूर्वानुमान और दबाव परीक्षण

बेस केस परिदृश्य में, सभी राज्यों को एक साथ मिलाकर, ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2021-22 और 2026-27 के बीच मध्यम रहने का अनुमान है (अंतर्निहित अनुमान अनुबंध 2 में दिए गए हैं)। अनुपात में कमी मुख्य रूप से कुछ राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और ओडिशा के शानदार वित्तीय प्रदर्शन के कारण है। अधिकांश अन्य राज्यों के 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। पंजाब के सबसे खराब स्थिति में रहने की उम्मीद है क्योंकि 2026-27 में इसका ऋण-जीएसडीपी अनुपात 45 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति में और गिरावट आएगी। राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल के 2026-27 तक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। इन राज्यों को अपने ऋण स्तरों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होगी (सारणी 8)।

सारणी 8: प्रमुख राज्यों के लिए प्रमुख संकेतक

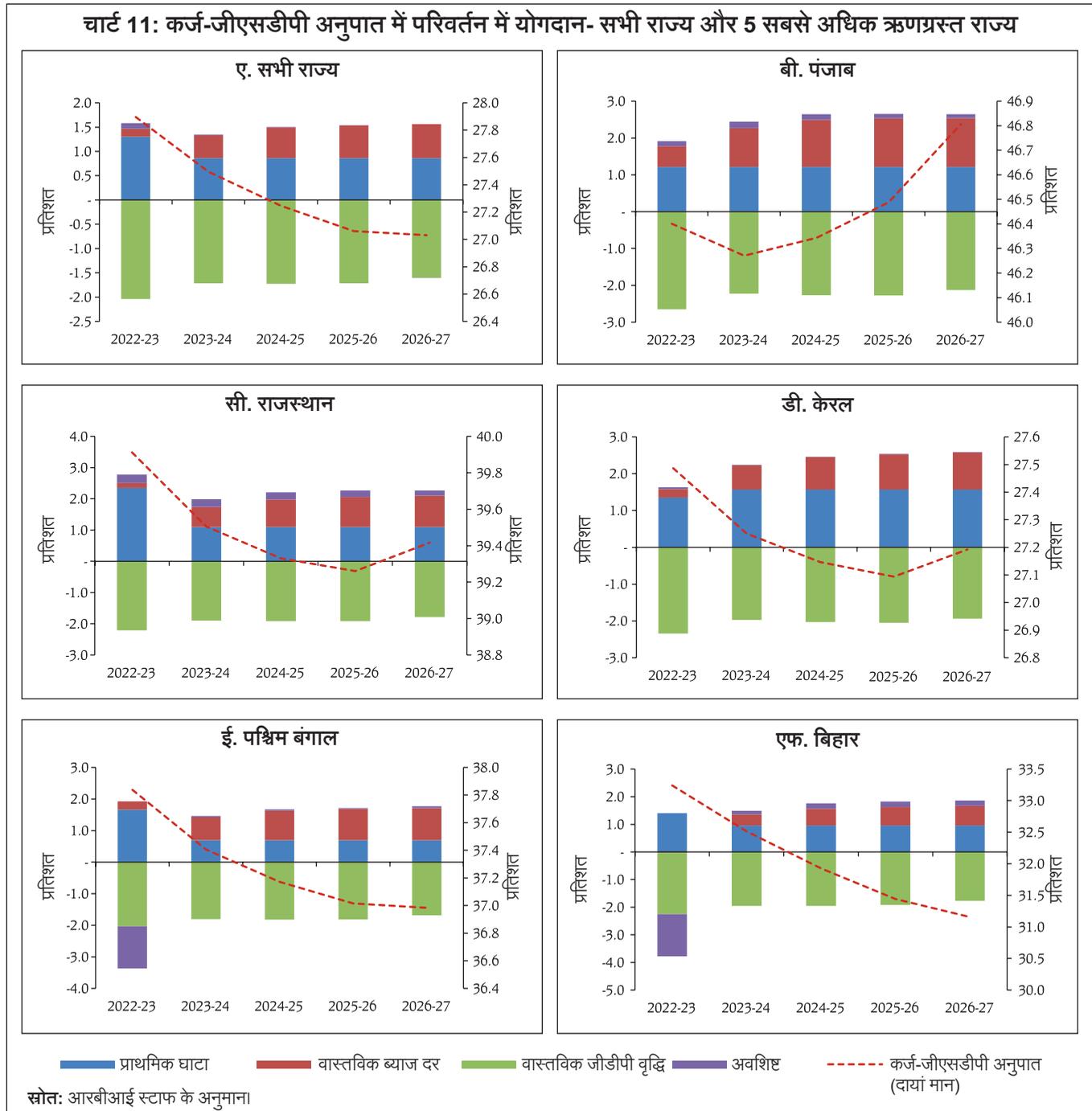
राज्य	पूर्वानुमान अवधि के लिए औसत (जीएसडीपी का प्रतिशत)		कर्ज-जीडीपी अनुपात		कर्ज-जीडीपी अनुपात में अंतर	अंतिम वर्ष (2026-27) परिदृश्य	
	प्राथमिक घाटा	सकल उधारी आवश्यकता	2019-20	2026-27		प्राथमिक घाटा	सकल उधारी आवश्यकता
आंध्र प्रदेश	2.2	6.1	31.7	33.9	2.2	2.3	1.6
असम	1.1	3.5	21.9	23.8	1.9	0.7	1.0
बिहार	1.0	3.8	32.6	31.2	-1.4	1.0	1.2
छत्तीसगढ़	1.1	3.6	24.9	29.7	4.7	0.9	0.6
गुजरात	0.6	2.1	20.2	16.6	-3.6	0.6	1.0
हरियाणा	1.6	5.3	28.1	31.1	3.0	1.7	1.3
झारखंड	1.1	3.9	29.4	30.2	0.8	1.1	1.1
कर्नाटक	1.3	3.2	20.8	22.6	1.8	1.3	1.0
केरल	1.5	5.1	31.3	38.2	6.9	1.6	0.9
मध्य प्रदेश	1.4	3.9	22.6	27.2	4.6	1.1	1.0
महाराष्ट्र	0.4	2.2	17.1	18.6	1.5	0.2	0.4
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	0.1	0.5	4.1	3.9	-0.2	-0.0	0.1
ओडिशा	0.3	2.2	26.2	19.7	-6.5	0.3	1.2
पंजाब	1.2	9.6	42.5	46.8	4.3	1.2	0.9
राजस्थान	1.3	4.7	35.4	39.4	4.1	1.1	0.9
तमिलनाडु	1.5	4.1	25.7	31.0	5.3	1.4	1.0
तेलंगाना	2.3	6.3	23.5	29.8	6.2	2.3	1.4
उत्तर प्रदेश	-0.2	2.7	32.6	27.3	-5.2	-0.2	0.7
उत्तराखंड	1.0	5.3	26.6	32.2	5.5	1.0	0.8
पश्चिम बंगाल	0.9	6.0	36.9	37.0	0.1	0.7	0.7
सभी राज्य*	0.9	3.9	26.0	27.0	1.1	0.9	0.9

*: सभी राज्यों में अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, जो सारणी में नहीं दिखाए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

एक साथ सभी राज्यों के लिए, कर्ज-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुकूल ब्याज दर - विकास अंतर (वास्तविक ब्याज दर और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के प्रभाव के बीच का अंतर) से

प्रेरित है जो प्राथमिक घाटे से ऋण के लिए उपार्जन को ऑफसेट करता है (चार्ट 11) उच्च मुद्रास्फीति के कारण पूर्वानुमान के शुरुआती वर्षों में गिरावट अधिक स्पष्ट है।¹⁹ यह पैटर्न मोटे तौर पर



¹⁹ वास्तविक ब्याज दर प्रभाव = {[सांकेतिक ब्याज दर - मुद्रास्फीति दर * (1 + जीएसडीपी वृद्धि)] * कर्ज - पिछले वर्ष में जीएसडीपी अनुपात} / {1 + जीएसडीपी वृद्धि + मुद्रास्फीति दर + जीएसडीपी वृद्धि * मुद्रास्फीति दर}

वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि प्रभाव = {(-) जीएसडीपी वृद्धि दर * कर्ज - पिछले वर्ष में जीएसडीपी अनुपात} / {1 + जीएसडीपी वृद्धि + मुद्रास्फीति दर + जीएसडीपी वृद्धि * मुद्रास्फीति दर}

पांच सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, पंजाब और राजस्थान के मामले को छोड़कर, जहां प्रारंभिक वर्षों में गिरावट के बाद कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है।

दबाव परीक्षण

राज्य के वित्त में कई तरह के अप्रत्याशित झटके आते हैं जो उनके वित्तीय परिणामों को बदल सकते हैं, जिससे उनके बजट और अपेक्षाओं के सापेक्ष फिसलन हो सकती है। कुछ राज्यों के लिए, झटके उनके कर्ज को एक महत्वपूर्ण राशि तक बढ़ा सकते हैं, जिससे राजकोषीय स्थिरता चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ काल्पनिक परिदृश्य पिछली घटनाओं और राज्यों के लिए जोखिम रेटिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। 5 सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों में, पंजाब और राजस्थान आकस्मिक देनदारियों की वसूली से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय झटके के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील प्रतीत होते हैं (सारणी 9)। वित्तीय पुनर्चना या बीमार डिस्कॉम के खैरात का भी इन दोनों राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पंजाब को छोड़कर, जो मुफ्त उपयोगिताओं के प्रावधान पर बड़ी राशि खर्च करता है, इन राज्यों के मामले में फ्रीबीज से वित्तीय जोखिम मध्यम प्रतीत होता है।

सारणी 9: विभिन्न परिदृश्यों के तहत जीएसडीपी के लिए कर्ज पर प्रभाव

राज्य	परिदृश्य 1 (आकस्मिक देयताएं पूरी तरह से लागू)	परिदृश्य 2 (उदय-जैसे डिस्कॉम का बेलआउट)	परिदृश्य 3 (स्वयं कर राजस्व वृद्धि आघात)	परिदृश्य 4 (उधार के माध्यम से वित्तपोषित सब्सिडी/ मुफ्त सुविधाएं)
बिहार	3.4	0.8	0.9	0.1
केरल	3.9	1.8	0.7	0.0
पंजाब	5.3	2.5	1	2.7
राजस्थान	8.6	3.7	0.4	0.6
पश्चिम बंगाल	0.9	0.9	0.7	1.1

टिप्पणी: परिदृश्य 1: यदि आकस्मिक देयताओं (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) को लागू किया जाता है, तो राजस्थान और पंजाब के जीएसडीपी अनुपात में कर्ज काफी सीमा तक बढ़ सकता है (क्रमशः 5.3 और 8.6 प्रतिशत अंक)।

परिदृश्य 2: उदय योजना जैसे बेलआउट के मामले में, यदि राज्य मार्च 2020 के अंत तक डिस्कॉम के 75 प्रतिशत ऋण का अधिग्रहण करते हैं, तो पंजाब, बिहार और राजस्थान के कर्ज का बोझ क्रमशः 2.5, 1.8 और 3.7 प्रतिशत बढ़ सकता है। **परिदृश्य 3:** पिछले दस वर्षों (2012-13 से 2021-22 तक) में राज्यों के जीएसडीपी अनुपात के लिए स्व-कर राजस्व के माध्यम से सभी ऋणात्मक विचलन के रूप में स्वयं के कर राजस्व आघात को न्यूनतम के रूप में लिया जाता है। जीएसडीपी के 1 प्रतिशत से भी कम पर स्वयं के कर राजस्व झटके का प्रभाव अपेक्षाकृत मामूली होगा। **परिदृश्य 4:** पूरी तरह से बाजार उधार के माध्यम से मुफ्त सुविधाओं के वित्तपोषण से सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों के वित्त पर हल्का से मध्यम प्रभाव आएगा।

स्रोत: राज्यों के बजट दस्तावेज; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिपोर्ट; और राज्य सरकारों से एकत्रित जानकारी।

V. निष्कर्ष

पड़ोसी देश श्रीलंका में हालिया आर्थिक संकट सार्वजनिक ऋण स्थिरता के महत्वपूर्ण महत्व की याद दिलाता है। भारत में राज्यों के बीच राजकोषीय स्थिति तनाव के निर्माण के चेतावनी संकेत दिखा रही है। स्वयं के कर राजस्व में मंदी, प्रतिबद्ध व्यय का एक उच्च हिस्सा और बढ़ते सब्सिडी बोझ ने राज्य सरकार के वित्त को कोविड-19 द्वारा बढ़ा दिया है। पांच सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों के लिए, ऋण स्टॉक अब टिकाऊ नहीं है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में ऋण वृद्धि ने उनकी जीएसडीपी वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। जोखिम के नए स्रोत सामने आए हैं - कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना; गैर-मेरिट फ्रीबीज पर बढ़ता खर्च; आकस्मिक देनदारियों का विस्तार; और डिस्कॉम का अतिदेय - रणनीतिक सुधारात्मक उपायों की गारंटी। तनाव परीक्षणों से पता चलता है कि सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और बिगड़ने की आशंका है, उनके ऋण-जीएसडीपी अनुपात के वर्ष 2026-27 में 35 प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है।

एक सुधारात्मक उपाय के रूप में, राज्य सरकारों को निकट भविष्य में गैर-योग्य वस्तुओं पर खर्च में कटौती करके अपने राजस्व व्यय को सीमित करना चाहिए। मध्यम अवधि में इन राज्यों को कर्ज के स्तर को स्थिर करने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा, बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार डिस्कॉम को घाटे को कम करने और उन्हें वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल बनाने में सक्षम बनाएगा। लंबी अवधि में, कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय की हिस्सेदारी बढ़ाने से दीर्घकालिक संपत्ति बनाने, राजस्व उत्पन्न करने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही, राज्य सरकारों को राजकोषीय जोखिम विश्लेषण करने और नियमित रूप से अपने ऋण प्रोफाइल पर दबाव परीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रावधान और अन्य विशिष्ट जोखिम शमन रणनीतियों को स्थापित करने में सक्षम हो सकें।

संदर्भ

Adams, C., Ferrarini, B. and Park, D. (2010). "Fiscal Sustainability in Developing Asia." *ADB Economics Working Paper*. Series No. 205, Mandaluyong City: Asian Development Bank.

Bohn, H. (1998). "The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits." *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963. <http://www.jstor.org/stable/2586878>

CRISIL (2022). 'Off-balance-sheet borrowings of states may have reached a decadal high of 4.5% of GSDP' May 04, 2022. Available at: <https://www.crisil.com/en/home/newsroom/press-releases/2022/05/off-balance-sheet-borrowings-of-states-may-have-reached-a-decadal-high-of-4-point-5-percent-of-gsdp.html>

Gopalan, R. (2013). "We understand the harmful effect of subsidies." Interview with economic affairs secretary, Business Standard, January 21, 2013.

Gulati, Ashok and Juneja Ritika (2022) "The poverty debate is an opportunity for food subsidy reforms", *Financial Express*, April 25, 2022.

IMF (2016). "Analyzing and Managing Fiscal Risks – Best Practices". IMF Policy Paper.

IMF (2000). "A Framework for Assessing Fiscal Vulnerability." *IMF Working Papers*

2000, 052, A001, available from: <https://doi.org/10.5089/9781451847246.001.A001> > [Accessed 11 June 2022]

Kaur, B., Mukherjee, A. and Ekka, A.P. (2018) "Debt sustainability of states in India: An assessment." *Ind. Econ. Rev.* 53, 93–129 (2018). <https://doi.org/10.1007/s41775-018-0018-y>

Singh, N.K. (2022). "In a free fall" *The Indian Express*. April 21, 2022. Available at: <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/freebies-are-a-passport-to-fiscal-disaster-7879244/>

Tiwari, A. (2012). "Debt Sustainability in India: Empirical Evidence Estimating Time-Varying Parameters." *Economics Bulletin*. 32. 1133-1141.

वेबसाइट:

<https://cag.gov.in/en>

<https://www.pfcindia.com/>

<https://www.business-standard.com/>

अनुबंध 1: राज्यों द्वारा घोषित वित्तीय सहायता/सब्सिडी की कुछ हालिया योजनाओं की सूची

क्र.	योजना	विवरण	वर्ष 2022-23 के लिए आबंटन (ब.अ.) (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार	स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के अनुसार
आंध्र प्रदेश						
1.	जगनन्ना अम्मावोडी	माता-पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों की माताओं को ₹15000 की वित्तीय सहायता	6,500	0.5	3.4	7.1
2.	वाईएसआर आसरा	11.04.2019 को एसएचजी के बकाया बैंक ऋणों की प्रतिपूर्ति	6,400	0.5	3.3	7.0
3.	बिजली सब्सिडी	कृषि के लिए/ बागवानी किसानों/ एकवा कल्चर किसानों को बिजली के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति/ रियायती बिजली आपूर्ति/ नकदी हस्तांतरण।	5000	0.4	2.6	5.5
4.	वाईएसआर चेतुथा	एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों से संबंधित 45-60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को उनकी आजीविका में सुधार के लिए ₹75,000 की वित्तीय सहायता।	4,236	0.3	2.2	4.7
5.	वाईएसआर रायथु भरोसा	एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रत्येक किसान परिवार (किरायेदार सहित) को ₹7500 और भूमिहीन किसानों को ₹13,500 की वित्तीय सहायता।	3,900	0.3	2.0	4.3
6.	वाईएसआर सुन्ना वड्डी पंटा रुनालु	किसानों को ₹1,00,000 तक के फसल ऋण के लिए ब्याज पर सब्सिडी।	500	0.0	0.3	0.5
7.	डॉ. वईएसआर आरोग्य आसरा	ऑपरेशन के बाद की रिकवरी अवधि के लिए रोगियों को ऑपरेशन के बाद भरण-पोषण भत्ते के रूप में ₹225 प्रति दिन की वित्तीय सहायता	300	0.0	0.2	0.3
8.	वाईएसआर वाहन मित्र	बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, मरम्मत, और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च को पूरा करने के लिए स्व-स्वामित्व वाले ऑटो/ टैक्सी ड्राइवरों को ₹10,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।	260	0.0	0.1	0.3
9.	धार्मिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	अर्चकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन एवं पारिश्रमिक निधि	120	0.0	0.1	0.1
		इमामों और मौजानों को प्रोत्साहन	126	0.0	0.1	0.1

(जारी)

क्र.	योजना	विवरण	वर्ष 2022-23 के लिए आबंटन (ब.अ.) (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार	स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के अनुसार
10.	वाईएसआर नेतन्ना नेस्तम	उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक हथकरघा मालिक बुनकर परिवार को ₹24,000/- प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।	199	0.0	0.1	0.2
कुल			27,541	2.1	14.4	30.3
बिहार						
1.	सशक्त महिला, सक्षम महिला	छात्राओं को सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए नकद प्रोत्साहन	900	0.1	0.5	2.2
2.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	प्रति छात्रा ₹3000 की वित्तीय सहायता	200	0.0	0.1	0.5
कुल			1,100	0.1	0.6	2.7
झारखंड						
1.	बिजली सब्सिडी	किसानों और गरीबों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली	4,855	1.2	5.8	19.5
		उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी	1,800	0.4	2.2	7.2
2.	गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र को बिना गिरवी रखे कम ब्याज दर पर ₹10 लाख तक का सॉफ्ट लोन।	-			
कुल			6,655	1.7	8.0	26.7
केरल						
1.	ब्याज सब्सिडी	सहकारी संस्थाओं से लिए गए कृषि ऋण की शीघ्र अदायगी पर	50	0.0	0.0	0.1
कुल			50	0.0	0.0	0.1
मध्य प्रदेश						
1.	बिजली सब्सिडी	किसानों और घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए	21,000	1.6	10.8	28.8
कुल			21,000	1.6	10.8	28.8
पंजाब ²⁰						
1.	बिजली सब्सिडी	हर घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली	5,000	0.8	5.2	13.4
2.	त्याग	बकाया बिजली बिल माफ करें।	-			

(जारी)

²⁰ धस्माना, आई. (2022)। "सभी राज्य आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं हैं कि वे मुफ्त उपहारों की घोषणा नहीं कर सकते।" बिजनेस स्टैंडर्ड, अप्रैल 2022। यहां उपलब्ध: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/not-all-states-are-so-financially-weak-that-they-can-t-announce-freebies-122041300560_1.html

क्र.	योजना	विवरण	वर्ष 2022-23 के लिए आबंटन (ब.अ.) (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार	स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के अनुसार
3.	महिलाओं को वित्तीय सहायता	महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक वयस्क महिला को ₹1000 की वित्तीय सहायता	12,000	1.9	12.6	32.1
कुल			17,000	2.7	17.8	45.4
राजस्थान						
1.	बिजली सब्सिडी	100 यूनिट से कम खपत करने वालों के लिए 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली और अधिक खपत वाले स्लैब के लिए रियायती दर	4500	0.3	2.1	4.6
2.	मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना	चिरंजीवी परिवारों की महिला प्रधानों को 3 वर्ष तक निःशुल्क स्मार्ट फोन का प्रावधान	2500	0.2	1.2	2.5
3.	छूट	कृषि ऋण माफी	1,000	0.1	0.5	1.0
4.	इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना	गर्भवती महिलाओं को दूसरे बच्चे के जन्म पर ₹6000 की वित्तीय सहायता	210	0.0	0.1	0.2
5.	मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, काली बाल भील और देवनारायण योजना	विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी का प्रावधान	170	0.0	0.1	0.2
6.	राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन	भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ₹5000 की वित्तीय सहायता	100	0.0	0.0	0.1
7.	ब्याज माफी योजना	मंडी शुल्क में छूट				
कुल			8,480	0.6	3.9	8.6
पश्चिम बंगाल						
1.	लक्ष्मी भंडारी	प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला को ₹1000 की वित्तीय सहायता और प्रत्येक दूसरी महिला को उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए ₹500	10,767	0.6	5.4	13.6
2.	कृषक बंधु	कृषक बंधु के तहत मृत किसान के परिवार को एकमुश्त अनुदान	500	0.0	0.3	0.6
		कृषि उद्देश्यों के लिए सभी किसानों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता	4,994	0.3	2.5	6.3

(जारी)

क्र.	योजना	विवरण	वर्ष 2022-23 के लिए आबंटन (ब.अ.) (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार	स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत के अनुसार
3.	कन्याश्री प्रकल्प:	लड़कियों को स्कूल में रहने और 18 साल की उम्र के बाद तक उनकी शादी में देरी सुनिश्चित करने के लिए ₹75 का वार्षिक प्रोत्साहन और ₹25,000 का एकमुश्त अनुदान।	1866.2	0.1	0.9	2.4
4.	रूपश्री प्रकल्प:	विवाह के प्रयोजन के लिए प्रति निर्धन महिला को ₹25000 की वित्तीय सहायता	750	0.0	0.4	0.9
कुल			18,877	1.1	9.5	23.8
हरियाणा						
1.	एससी/बीपीएल/बीसी छात्रों को मासिक वजीफा	छात्रों के शैक्षिक अवसरों में सुधार करने और उनके प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन।	242	0.0	0.2	0.3
3.	मुख्यमंत्री मंती विवाह शगुन योजना	गरीब परिवारों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता।	180	0.0	0.2	0.2
4.	आपकी बेटि, हमारी बेटि (लाइली) योजना	अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों को पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर ₹21,000 की वित्तीय सहायता।	160	0.0	0.2	0.2
5.	कॉलेज के छात्रों को वजीफा	राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के सभी छात्रों के उत्थान और कल्याण के लिए ₹1000 प्रति माह का वजीफा।	45	0.0	0.0	0.1
6.	मुफ्त साइकिलें	कक्षा IX से XII में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क साइकिल का प्रावधान।	6	0.0	0.0	0.0
7.	अनुसूचित जाति परिवार मत्स्य पालन क्षेत्र के कल्याण के लिए योजना	राज्य में अधिसूचित जल क्षेत्र के मत्स्य कृषकों, मछुआरों एवं मत्स्य ठेकेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।	5.6	0.0	0.0	0.0
कुल			638.6	0.1	0.6	0.9

टिप्पणी: पंजाब के लिए डेटा 2021-22 से संबंधित है जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 2022-23 (ब.अ.) से संबंधित है।

स्रोत: राज्यों के बजट दस्तावेज।

अनुबंध 2: राज्य स्तरीय कर्ज धारणीयता मॉडल के लिए अनुमान

चर	मान्यताओं
स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	<ul style="list-style-type: none"> वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 18 राज्यों का डेटा सीधे एमओएसपीआई से प्राप्त किया है। सभी राज्यों का औसत जीएसडीपी इन 18 राज्यों के भारित औसत के समान माना जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, आईएमएफ के पूर्वानुमानों के आधार पर सभी राज्यों की समेकित जीएसडीपी बढ़ने का अनुमान है। वृद्धि दरों में अंतर-राज्यीय अंतरों का हिसाब यह मानकर लगाया जाता है कि पूर्वानुमान अवधि में राज्य का सापेक्ष वृद्धि निष्पादन 2014-15 से 2018-19 की अवधि के 5 वर्षों के औसत का पालन करेगा।
जीडीपी अपस्फीतिकारक पर आधारित मुद्रास्फीति	<ul style="list-style-type: none"> वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, 18 राज्यों का डेटा सीधे एमओएसपीआई से प्राप्त किया जाता है। शेष राज्यों के लिए इन 18 राज्यों की औसत मुद्रास्फीति कल्पित की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, मुद्रास्फीति आईएमएफ अनुमानों पर आधारित है। सभी राज्यों में समान मुद्रास्फीति कल्पित है।
प्राथमिक घाटा	<ul style="list-style-type: none"> वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 23 राज्यों का डेटा सीधे बजट से प्राप्त किया है। शेष राज्यों के लिए, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य का प्राथमिक घाटा 2009-10 से 2018-19 तक 10 साल की अवधि का ऐतिहासिक औसत माना जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य के प्राथमिक घाटा (उदय योजना के तहत डिस्कॉम बेलआउट के एकमुश्त प्रभाव को समाप्त करने के बाद) को 2009-10 से 2018-19 तक 10 साल की अवधि का ऐतिहासिक औसत माना जाता है। आंध्र प्रदेश के लिए, 2014-15 को राज्य के विभाजन के वर्ष को देखते हुए औसत से बाहर रखा गया है। तेलंगाना के लिए पूर्वानुमान अवधि का अनुमान लगाने में 2015-16 से 2018-19 के औसत पर विचार किया है।
ब्याज दर	<ul style="list-style-type: none"> अप्रैल और मई 2022 में बोलियों में प्राप्त मूल्य के आधार पर 2022-23 में नए उधार पर 7.3 प्रतिशत प्रतिफल होने का अनुमान लगाया गया था। मुद्रास्फीति में कमी आने के साथ 2026-27 तक प्रतिफल धीरे-धीरे घटकर 6.9 प्रतिशत हो गया।